

अधिकारतंत्र का राजनीतिकरण, दुष्परिणाम तथा उपाय

डॉ. जावेद अख्तर

सहायक प्रोफेसर

राजकीय पीजी कॉलेज, छर्ना, अलीगढ़

सारांश: स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रारंभिक दशकों में जिन राजनेताओं के पास राज्य की सत्ता आई वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में तपे-बढ़े आदर्शवादी जननेता थे। उनके मन में एक नया, बेहतर और विकसित देश बनाने का आतुरक उत्साह था। इस कार्य में उनको सहायता करने के लिए उन्हें एक अनुभवी, अखिल भारतीय, अनुशासित और नियमित प्रशासन तंत्र विरासत के रूप में मिला गया। हालांकि विदेशी शासकों ने इस तंत्र को अपने औपनिवेशिक हितों के लिए बनाया था पर नव स्वतंत्र भारत के महान नेताओं ने इस तंत्र की प्रशासनिक क्षमता को पहचाना और नई प्रेरणा देकर उसे कानून-व्यवस्था के साथ-साथ देश के विकास कार्यों का संचालन करने का दायित्व भी सौंप दिया। इस दौर में प्रशासनिक अधिकारियों के मन में भी अपने देश को विकसित करने का नया उत्साह था और उन्होंने अपने नए दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया।

मुख्यशब्द: अधिकारतंत्र का राजनीतिकरण, दुष्परिणाम तथा उपाय

प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रारंभिक दशकों में जिन राजनेताओं के पास राज्य की सत्ता आई वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में तपे-बढ़े आदर्शवादी जननेता थे। उनके मन में एक नया, बेहतर और विकसित देश बनाने का आतुरक उत्साह था। इस कार्य में उनको सहायता करने के लिए उन्हें एक अनुभवी, अखिल भारतीय, अनुशासित और नियमित प्रशासन तंत्र विरासत के रूप में मिला गया। हालांकि विदेशी शासकों ने इस तंत्र को अपने औपनिवेशिक हितों के लिए बनाया था पर नव स्वतंत्र भारत के महान नेताओं ने इस तंत्र की प्रशासनिक क्षमता को पहचाना और नई प्रेरणा देकर उसे कानून-व्यवस्था के साथ-साथ देश के विकास कार्यों का संचालन करने का दायित्व भी सौंप दिया। इस दौर में प्रशासनिक अधिकारियों के मन में भी अपने देश को विकसित करने का नया उत्साह था और उन्होंने अपने नए दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया।

पर प्रारंभिक दौर के इन नेताओं के जाने के बाद देश की राजनीति का स्वरूप बदलने लगा। देशभक्ति, सेवा और समर्पण की राजनीति धीरे-धीरे सत्ताकामी चुनावी राजनीति में परिवर्तित हो गई। बाद के अधिकांश राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य येन-केन-प्रकारेण, अर्थात् छल-कपट से, लोक लुभावन पर झूठे वादों से, गुटबाजी से, किसी प्रकार बहुमत प्राप्त कर सत्ता हथिया लेना और उस पर काबिज होकर बने रहना हो गया। इस राजनीति में सत्ता, पद और अधिकारियों का उपयोग जनकल्याण के लिए कम अपने और अपनों का हित करने के लिए अधिक होने लगा। इन भ्रष्ट नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए लोक-प्रशासकों की सहायता आवश्यक थी। अतः उन्हें भय या लोभ दिखाकर अपनी ओर झुका लिया गया। लोक-प्रशासकों ने भी भ्रष्ट नेताओं की हाँ में हाँ मिलाने में ही अपनी भलाई समझी। आखिर पानी में रहकर मगर से बैर करना कौन चाहेगा? एक प्रकार से प्रशासन तंत्र का राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता साथ-साथ हो गए।

एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्थायी कार्यपालिका का अधिकारी तंत्र राजनीति निरपेक्ष होता है। जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसकी नीतियों के अनुरूप उनके कार्यक्रमों को अधिकरण एवं ईमानदारी से, नियमानुसार और लोकहित को ध्यान में रखकर करते हैं।

पर जब इसी का राजनीतिकरण हो जाता है तो ऐसा नहीं हो पाता। प्रशासनिक तंत्र को संवैधानिक व्यवस्था की नियम मर्यादाएँ, राजकोष की सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था के तौर-तरीके आदि भली-भाँति मालूम होते हैं। यदि राजनैतिक कार्यपालिका इनके विपरीत कोई काम करने का प्रयास करती है तो अधिकारीगण उन्हें टोकते हैं, आगाह करते हैं और जमीन हकीकत से अवगत कराते रहते हैं। पर जब उनका राजनीतिकरण हो जाता है तो तब वे वही करते हैं जो मंत्रीगण सुनना चाहते हैं। तब गलत निर्णय ले लिए जाते हैं जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है। अधिकारियों और मंत्रियों की मिलीभगत से बड़े-बड़े घोटाले होते हैं। सरकार के बड़े-बड़े ठेके गुणवत्ता के आधार पर नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी को 'किकबैक' राशि के लिए जाने लगते हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग राजनीतिक प्रभाव पर, पैसा बनाने के लिए, या भ्रष्टाचार में संलिप्त ईमानदार अधिकारियों को गुट से हटाने के लिए किया जाने लगता है। सुशासन के स्थान पर देश कुशासन और भ्रष्टाचार के दुष्चक्र में फँस जाता है तथा देश का विकास बाधित हो जाता है।

सार्वजनिक जीवन को इन व्याधियों से बचने का सबसे कारगर तरीका है, प्रशासनिक अधिकारियों के आंतरिक व्यक्तित्व का परिष्कार और उनका सशक्तिकरण ताकि वे भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण आदि के दुष्प्रभावों का सामना कर सकें। उनका चरित्र, मूल्यनिष्ठा, देशभक्ति और संविधाननिष्ठा इतनी सुदृढ़ हो कि वे भय और प्रलोभन से विचलित हुए बिना लोकसेवा के मार्ग पर डटे रहें। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि राजनीतिक द्वेषजन्य कार्यवाहियों से उन्हें सुरक्षित रखने वाले प्रावधानों को और मजबूत किया जाए ताकि ईमानदार और मूल्यनिष्ठ अधिकारी निडर होकर लोकहित की रक्षा के लिए तत्पर रह सकें।

उदाहरण के रूप में प्रस्तुत

एक सीमांत राज्य के एक जिले में मादक (नशीले पदार्थों) का खतरा अनियंत्रित हो गया है। इसके परिणामस्वरूप कालेधन का प्रचलन, मौत की घटनाएँ में वृद्धि, हथियारों की तस्करी, व्यापक हो गई है तथा शिक्षा व्यवस्था लगभग ठप पड़ गई है। सम्पूर्ण व्यवस्था एक प्रकार से समाप्ति के कगार पर है। इन सब खबरों से कि स्थानीय राजनेता और कुछ पुलिस उच्चाधिकारी भी इस माफिया को गुप्त संरक्षण दे रहे हैं, स्थिति और भी बदतर हो गई है। ऐसे समय में, परिस्थिति को सामान्य करने के लिए, एक महिला पुलिस अधिकारी, जो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने कौशल के लिए जानी जाती है, को पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

यदि आप वही पुलिस अधिकारी हैं तो संकट के विभिन्न आयामों को चिन्हित कीजिए। अपनी समझ के अनुसार, संकट का सामना करने के उपाय भी सुझाइए।

नशाखोरी की समस्या के विभिन्न आयाम

1. नशीले पदार्थों की गिरफ्त में आकर युवा पीढ़ी शारीरिक और मानसिक तौर पर अक्षम, अकर्मण्य और ऊर्जाहीन होती जा रही है। उनकी शिक्षा-दीक्षा और उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। साथ ही समाज को उनकी योग्यता और कौशल का लाभ नहीं मिल पाता या कम रह जाता है।
2. पैसा जुटाने के लिए नशेड़ियों द्वारा चोरी-छिन्नी तथा अन्य आपराधिक घटनाएँ बढ़ रही हैं।
3. नशीले पदार्थों का धंधा बड़े-बड़े ड्रग माफियाओं द्वारा संचालित हो रहा है। ये माफिया अन्य आपराधिक कार्यों में भी लिप्त होते हैं। इनका धंधा पूर्णतः कालेधन की कमाई से चलता है। प्रायः इनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं।

4. जिस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है उसे देखते हुए बहुत संभव है कि ड्रग माफिया को कुछ-एक भ्रष्ट राजनेताओं और अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हो। इन सभी पक्षों को ध्यान में रखकर नशाखोरी रोकने के उपाय किए जाने चाहिए।

समस्या का सामना करने के उपाय

इस समस्या के दो पक्ष हैंकृ 1. मानवीय पक्ष और 2. अपराध नियंत्रण का पक्ष।

1. मानवीय पक्ष

नशाखोरी में फँसने वाले युवक हमारे-आपके बेटे-बेटियाँ हैं। वे हमारे परिवारों के भविष्य हैं, समाज के और देश के भी भविष्य हैं। नशाखोरी से बर्बाद होती उनकी जिंदगीयाँ हम सभी के लिए पीड़ादायक हैं। अतः हम सभी कोकृ अभिभावकों, शिक्षकों, पुलिस अधिकारियोंकृ को मिलकर इस समस्या से लड़ना चाहिए। इसके लिए एक ऐसी प्रभावी नशाविरोधी मुहिम चलाई जानी चाहिए जो नशाखोरी के भयावह परिणामों का भावनात्मक चित्रण इस प्रकार करे कि युवाओं में उससे विरत रहने की इच्छाशक्ति जागृत हो जाए। इस तरह की लघु फिल्मों, पोस्टरों, कहानियों आदि के माध्यम से युवाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस कार्य में स्कूल, कॉलेजों की विशेष भूमिका होनी चाहिए।

दूसरी ओर वे युवा जो इसमें फँस चुके हैं उन्हें इससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्हें उचित मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आजकल ऐसे कम-कंकपबजपवद बमदजतम स्थापित हो रहे हैं जहाँ नशाखोरी को एक प्रकार का रोग मानकर दवाइयों और परामर्श द्वारा उसका उपचार किया जाता है। इस प्रकार में अभिभावकों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। नशे में फँसे बच्चे की भर्त्सना, डाँट-डपट करने के बजाय उसे प्रेम से अपनाकर अपनी लत से उबरने में उसकी सहायता करनी चाहिए। उसका मनोबल बनाए रखना चाहिए। एक महिला पुलिस अधिकारी इस

2. अपराध नियंत्रण पक्ष

मादक पदार्थों का सेवन करना, उन्हें अपने पास रखना, उन्हें बेचना या दूसरों को उपलब्ध कराना या घोर आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहना, ये सभी दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। अतः इनकी रोकथाम के लिये सम्बन्धित विभागों द्वारा सामान्य कर कार्य करना चाहिए तथा दण्डित करना चाहिए। इन सभी कार्यों में पुलिस विभाग द्वारा ईगानदारी व गुस्तैदी से कार्य करना चाहिए तथा साहसी पुलिस अधिकारियों को राजनीतिक प्रत्योसाहस भी मिलना चाहिए।

अतः यह कहना भी सत्य ही होगा कि यदि वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने जिस साहस से उ0प्र0 में अपराध नियंत्रण किया है उसकी सराहना करनी चाहिए।

शोध संदर्भ

1. लोक प्रशासन में नैतिक व मानवीय मूल्य, 196, 197 अजित नारायण त्रिपाठी Page – 198, 199 NEW AGE INTERNATIONAL LIMITED, NEW DELHI
2. Naresh Chandra Saxena, What Ails the IAS and why it Fails to Deliver, An Insider View Sage Publications India, New Delhi, 2019

3. Prashant Kumar Mishra, In Quest of Meaningful Life, An Autobiography of a Civil Servant, Konark Publication, New Delhi
4. Vinod Rai, Not Just an Accountant, Rupa Publication, New Delhi